भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1357
दिनांक 11 फरवरी, 2025 के लिए प्रश्न

दुग्ध उत्पादन

1357. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री नरेश गणपत म्हस्केः
श्री राजेश वर्माः
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः
श्रीमती शांभवीः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) के घटक ए के कार्यान्वयन के बाद महाराष्ट्र और बिहार के संबंध में दुग्ध उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि का आंकड़ा है;

(ख) घटक बी के अंतर्गत महाराष्ट्र और बिहार में संगठित डेयरी सहकारी समितियों की संख्या क्या है और इन राज्यों में किसानों की आय में सुधार में इनका क्या योगदान है;

(ग) क्या एनपीडीडी के अंतर्गत निधि के आवंटन ने महाराष्ट्र और बिहार में विशेष रूप से ग्रामीण डेयरी सहकारी समितियों में दूध की बर्बादी को कम करने और दूध की गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है;

(घ) क्या महाराष्ट्र और बिहार में घटक बी के अंतर्गत विपणन अवसंरचना का विस्तार छोटे पैमाने के डेयरी किसानों के लिए संगठित बाजारों की पहुंच को बढ़ाने में सहायक रहा है; और

(ङ) क्या सरकार महाराष्ट्र और बिहार में डेयरी अवसंरचना और प्रसंस्करण क्षमताओं में क्षेत्रीय विषमताओं का समाधान करने के लिए एनपीडीडी को और अधिक सुदृद्ध करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ड़) पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार फरवरी 2014 से पूरे देश में "राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)" योजना को कार्यान्वित कर रहा है। जुलाई 2021 में इस योजना को वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक के लिए दो घटकों के साथ पुनर्गठित/पुनर्संरेखित किया गया है:-

(i) एनपीडीडी का घटक 'क' गुणवत्तायुक्त दूध परीक्षण उपकरणों के साथ-साथ प्राथमिक प्रशीतन सुविधाओं के लिए अवसंरचना के सृजन/सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है।
(ii) एनपीडीडी योजना के घटक 'ख' "सहकारिता के माध्यम से डेयरी" का उद्देश्य संगठित बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाकर, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना को उन्नत करके दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री में वृद्धि करना है।
एनपीडीडी एक मांग आधारित योजना है और महाराष्ट्र तथा बिहार सहित सभी राज्य योजना दिशानिर्देशों के अनुसार डेयरी अवसंरचना की कमियों को दूर करने के लिए अपने परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। बिहार घटक क और ख दोनों के अंतर्गत आता है, जबकि महाराष्ट्र केवल घटक क के अंतर्गत आता है।
ग्राम स्तर पर नई डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करके डेयरी सहकारी समितियों का कवरेज बढ़ाने से किसानों की संगठित बाजार तक पहुंच में सुधार करने में मदद मिलती है और इस प्रकार डेयरी किसानों की आय में वृद्धि होती है। इसी तरह, दूध प्रशीतन अवसंरचना के निर्माण/सुदृढ़ीकरण, डीसीएस/गांव/जिला/राज्य स्तरीय दूध परीक्षण प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण और जागरूकता सृजन आदि ने महाराष्ट्र और बिहार में दूध की बर्बादी को कम करने और दूध की गुणवत्ता में सुधार करने में योगदान दिया है।

राज्य तथा पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं/पहलों के अलावा, एनपीडीडी योजना ने महाराष्ट्र और बिहार में दूध उत्पादन बढ़ाने में भी योगदान दिया है। एनपीडीडी योजना के घटक क के कार्यान्वयन के बाद से महाराष्ट्र और बिहार में दूध उत्पादन की मात्रा और इसकी प्रतिशत वृद्धि संबंधी आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

राज्य	**दूध उत्पादन ('000 टन में)**		**% वृद्धि**
	वर्ष 2020-21*	**वर्ष 2023-24**	
महाराष्ट्र	13,703.32	16,045.41	17.09
बिहार	11,501.58	12,852.99	11.75

***** पुनर्गठित एनपीडीडी योजना का आधार वर्ष

बिहार में घटक ख के अंतर्गत 10 प्रतिभागी संस्थाओं (पीआई) के लिए कुल 12 परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है, जिसका कुल परिव्यय 117.20 करोड़ रुपये (ऋण- 55.01 करोड़ रुपये, अनुदान- 53.05 करोड़ रुपये, पीआई का योगदान- 9.14 करोड़ रुपये) है। एनपीडीडी के घटक-ख के अंतर्गत बिहार में संस्वीकृत कुल डेयरी सहकारी समितियों, नए दूध प्रसंस्करण संयंत्रों की क्षमता और दूध विपणन अवसंरचना का विवरण नीचे दिया गया है:

राज्य - बिहार	**संस्वीकृत अवसंरचना**
नई डेयरी सहकारी समिति	1180
नवीन/विस्तार/आधुनिकीकरण दूध प्रसंस्करण संयंत्र/मूल्य वर्धित उत्पाद (टीएलपीडी)	157.28
दूध पार्लर	68
डीप फ़्रीज़र	3100
विज़ी कूलर्स	355
टीएलपीडी - हजार लीटर प्रतिदिन	

एनपीडीडी योजना के घटक ख के अंतर्गत विपणन अवसंरचना के विस्तार से बिहार के दूध संघों/इकाइयों को शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण स्तर पर विपणन मार्गों का विस्तार करने का अवसर मिला है और डेयरी उत्पादों की बिक्री से संबंधित उनके कोल्ड चेन अवसंरचना को सुदृढ़ किया गया है, जिससे छोटे पैमाने के डेयरी किसानों के लिए संगठित बाजारों तक पहुंच बढ़ गई है।

*****